

ग्रामीण विकास की रणनीतियां और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एक अध्ययन

Sangeeta Sharma

Vice Principal

JP Global of school.

भारत गाँवों का देश है। जिसकी लगभग 72% आबादी गांव में रहती है। भारत की जनसंख्या का कुछ भाग शक्तिशाली एवं समृद्ध हो सकता है परन्तु हमारे गांव गरीबी है जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत की प्रगति का कोई भी अर्थ नहीं है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गम तथा निरंतर विकास के लिए प्रयत्नरत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन में लगा हुआ है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनता के योग्य बनाकर उनके जीवन स्तर को सुधारना है, गरीबी दूर करना तथा सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ विकास कार्यक्रमों को समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग तक पहुंचाने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ पेयजल ग्रामीण आवास तथा सड़क संपर्क के उच्च अधिकारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। निराश्रित और गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को भी काफी महत्व दिया जा रहा है।

ग्रामीण विकास एक परिचय:-

ग्रामीण विकास के लोगों के लिए कृषि एक आजीविका का मुख्य साधन है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति से तात्पर्य शहरी औद्योगिक केन्द्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है, यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़े-बड़े तथा सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों से युक्त शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं। फिर भी ग्रामीण विकास को इतना ही अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, इसका उत्तर आज भी यही है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी ही है कि उसे सब का निर्वाह नहीं हो पाता। इसी कारण से देश की एक चौथाई जनता अभी भी गरीबी रेखा के नीचे में रहती है यदि हम भारत के वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। ग्रामीण विकास से तात्पर्य है यही है ग्रामीण

विकास एक व्यापक शब्द है यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक विकास में पीछे रह गए हैं।

जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक विकास में पीछे गए हैं। भारत की विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नहीं और सार्थक पाल करने की आवश्यकता बनी है। वह इस प्रकार हैं मानव संसाधनों का विकास जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

साक्षरता विशेष पर नारी साक्षरता शिक्षा उन कौशल का विकास

स्वास्थ्य जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य एवं दोनों शामिल है

भूमि सुधार

प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संस्थाओं का विकास

आंतरिक संरचना का विकास जैसे बिजली सिंचाई साथ रन परिवहन सुविधा ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोशाक सड़क बनाना कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना को सुविधा

निर्धनता निर्वहन और समाज के कमजोर लोगों को जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय

जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर पर गाने का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र को में साथ विपणन सह कृषि अर्थव्यवस्था को समृद्ध समय-समय पर कृषि और गैर सरकारी कार्य में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। खेतों में बीजारोपण से प्रश्न पकाने के बाद संबंध होने तक अवधि बहुत लंबी होती है। इसी कारण से किसानों के बीच उर्वरक औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यही नहीं उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह करने के लिए शादी मृत्यु एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी कर्ज का ही सहारा रहता है। स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारिक छोटे सीमांत किसानों को और भूमि मजदूरों से बहुत उच्च ब्याज के रसूल ने और ऋण खाता में हेरा फेरी करने का ऐसा कुचक चला रहे थे। जो की ऋण मुक्ति किस कभी नहीं हो पाए थे। भारत में 1970 में सामाजिक बैंक के आरंभ कर इस व्यवस्था पर एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया गया।

ग्रामीण साहब का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत संस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया आगे चलकर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के संबंध में ⁴⁹के लिए एक शीर्ष संस्थान है हरित क्रांति के लिए भी ग्रामीण साहब व्यवस्था में बहुत बड़े

परिवर्तन एवं सूत्रपात किए गए क्योंकि इससे ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों उत्पादों को मुख्य विविधता प्रदान करे

कृषि विपणन व्यवस्था हम जो भी अनाज फल सब्जियां आदि रोज कहते हैं। वह देश के अलग-अलग क्षेत्र से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंच जाते हैं। कृषि वितरण व्यवस्था व व्यवस्था है जिसमें देशभर से उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रह भंडारण प्रसंस्करण परिवहन पैकिंग वर्गीकरण और वितरण अधिक किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन भेजते समय किसानों को टोला में हेरा फेरी तथा खाते में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। प्राय किसानों को बाजार में प्रसिद्ध भावों का पता नहीं होता तो उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छे भंडार में सुविधा भी नहीं होती थी। अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं कर पाते थे 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के भाव में क्षतिग्रस्त हो जाता था, इसीलिए सरकार ने इसे निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण विधि कारण एक पहलू फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन करने से संबंधित है।

दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेती से हटकर अन्य संबंधी कार्य जैसे पशुपालन मुर्गी पालन मत्स्य पालन आदि तथा गैर क्षेत्र में लगाना इस विधि कारण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है, क्योंकि किसी खेती के आधार पर राजीव का कमाने से जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। विविधीकरण द्वारा हम केवल खेती की जोखिमों को कम करने में सफल होंगे बल्कि ग्रामीण जनसंख्या उत्पादक वैकल्पिक भारतीय आजीविका किंतु रवि की फसल के मौसम में पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं होना। उन क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। कृषि क्षेत्र तो पहले से ही बहुत भोज है। अतः बढ़ती भी श्रम शक्ति के लिए अन्य गैस सरकारी कार्यों के वैकल्प रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। कृषि संस्करण उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चरण उद्योग तथा पशुपालन भारत के किस समुदाय प्राइवेट मिश्रित कृषि पशु धन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। इसमें गाय भैंस बकरी भेड़ आदि का पशुपालन के द्वारा जीवन निर्भय के साधन होते हैं।

मत्स्य पालन मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलसागर को मन यह दाता मानते हैं। सागर महासागर संहिताएं होते हैं। जिले प्राकृतिक तालाब पराबादी सभी जलाकर मच्छरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक जल संचयन और मत्स्य पालन एवं

प्रौद्योगिकरण के प्रवेश के बाद मत्स्य उद्योग में विकास की नई मंजिलें तय की है। आजकल देश के मत्स्य पालन लगभग 65% क्षेत्र में तथा 35% महासागरीय क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है अन्य रोजगार आजीविका विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय व्यवस्था का अनेक क्षेत्रों का में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। किस शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धार्मिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णय योगदान दे सकती है सूचनाओं के उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य सुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्र का समय रहते पूर्ण लगा सकती है। इस तरह से समाजसेवी पत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से सम्मानित करने में सफल हो सकते हैं। ध्वनि विकास और जैविक कृषि भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक और विश्व जन कीटनाशकों पर आधारित है। यह विषाक्त तथा हमारी खाद्य पूर्ति के लिए जल स्रोतों से निर्धारित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही इसके कारण मुक्त प्रवर्तक सीन हो जाती है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। अतः विकास की धारणीयता के लिए पर्यावरण मित्र औद्योगिक विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए हैं। कृषि जैविक के लाभ जैविक कृषि महंगे शंकर विधियों रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक प्रयोग पर निर्भर होती है। यह सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश में प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजार में जैविक कृषि उत्पादन की बढ़ती बीमा के कारण उनके अर्थ में अच्छी आए हो सकती है।

ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ और सामाजिक परिवर्तन एक अध्ययन। एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों को संदर्भित करता है। सामाजिक परिवर्तन, समाज में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जो ग्रामीण विकास के परिणामस्वरूप या अन्य कारकों के कारण हो सकते हैं।

ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ और सामाजिक परिवर्तन:-

ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ और सामाजिक परिवर्तन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों को संदर्भित करता है। सामाजिक परिवर्तन, समाज में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जो ग्रामीण विकास के परिणामस्वरूप या अन्य कारकों के कारण हो सकते हैं।

ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ:

ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ व्यापक हैं और इसमें विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे

कृषि विकास:

किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना।

बुनियादी ढांचे का विकास:

सड़कों, बिजली, पानी, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

सामाजिक विकास:

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में सुधार करना।

आर्थिक विकास:

ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाना।

पर्यावरण संरक्षण:

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना।

सामाजिक परिवर्तन:

ग्रामीण विकास रणनीतियों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में कई सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जैसे:

शिक्षा का प्रसार:

शिक्षा के प्रसार से ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि होती है, जिससे लोगों को बेहतर अवसर मिलते हैं।

स्वास्थ्य में सुधार:

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और जागरूकता से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों और मृत्यु दर में कमी आती है।

महिला सशक्तिकरण:

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति में सुधार होता है।

सामाजिक समानता में वृद्धि:

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक असमानता कम होती है, जिससे सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं।

आर्थिक विकास:

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास से गरीबी और बेरोजगारी में कमी आती है।

ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ और सामाजिक परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन रणनीतियों को लागू करके, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, और एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ समाज का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण:

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम):

यह एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):

यह एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके और उन्हें कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।

वर्तमान में संचालित ग्रामीण विकास की योजनाएं

जन सहयोग एवं प्रौद्योगिकी व विकास परिषद यह परिषद ग्रामीण विकास के निम्नलिखित कार्य में सहायता प्रदान करती है ।

ग्रामीण विकास में सम से भी कार्यों को प्रोत्साहन

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाना

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति

केंद्रीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम गरीब

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में संभावित लोगों के संगठन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

स्वरोजगार योजनाएं

ग्राम प्रौद्योगिकी विकास विकलांगों का पुनर्वास ग्रामीण सुरक्षित पेयजल आपूर्ति

ऐसे गांव जहां युक्त संगत दूरी लगभग सैकड़ों किलोमीटर की होती है । वहां पेयजल एवं सुनिश्चित स्रोत उपलब्ध कराने की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है । त्वरित ग्रामीण जिला पूर्ति कार्यक्रम इसके अंतर्गत उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित के सदस्यों प्रधान गांव में जल पूर्ति को सुनिश्चित कर पांचवी वर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है ।

राजीव गांधी राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत भूमि जल अन्य प्राकृतिक संस्थाओं का संरक्षण और विकास और सदुपयोग समाज के लिए कमजोर उपेक्षित वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारना एवं कार्यक्रमों के साथ संबंध में स्थापित करना ।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत भारत के मरुस्थलीय प्रति के लिए जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना एवं पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पौधारोपण मृदा आद्रता संरक्षण तथा जल विकास के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करना होता है ।

कंप्यूटर का ग्रामीण सेवा ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने कर्मचारी ग्रामीण सूचना प्रणाली की शुरुआत की थी इसका कार्य डीआरडीए में एक मिली कंप्यूटर केंद्र की स्थापना करना है ।

इस सेवा का उद्देश्य विभिन्न बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं उनके मॉनेटरी प्रणाली को सशक्त बनाना है । ग्रामीण टेलीफोन सेवा ग्रामीण टेलीफोन सेवा पंचायत के टेलीफोन सेवा प्रदान करने की जिसमें एसटीडी की सुविधा उपलब्ध डीटीएच अपने गांव को वायरलेस और अन्य सुविधा से जोड़ा है । टेलीफोन कनेक्शन के लिए गांव के लिए सुरक्षित जमा राशि को ₹500 से घटकर शून्य किया गया । अभी तक भारत के लगभग 60% गांव को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण संचार सेवक योजना

अप्रैल 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में डाकबियों के लिए दूर संख्या से सुविधा खोज करता है ग्राम पुरस्कार योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2003 को पोषित योजना का उद्देश्य स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों लोगों को ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना होता है ।

रोलर सैनिटेशन प्रोग्राम ग्रामीण स्वच्छता हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत सदस्य स्वच्छता गृह सफाई सुरक्षित जल कचरा अपशिष्ट जल विकास सम्मिलित है ।

सामाजिक तहसील तक के परिणाम सामाजिक गतिशीलता के अच्छे और पूरे दोनों परिणाम निकलते हैं । इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि इसे योगी व्यक्ति उचित स्थान प्राप्त करके सफल हो जाते हैं । इससे लोगों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है । इससे समाज के विकास का प्रगति होता है । उसे समझ में प्रगति के अवसर बढ़ाते हैं । सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है । इससे कल्याणकारी कार्य करके उन्हें आगे बढ़ाने एवं नवीन सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित करने की प्रेरणा मिलती है । किंतु सामाजिक गतिशीलता सदैव ही लाभकारी परिणाम नहीं देती वर्णन यह कभी-कभी समाज के लिए कई कुछ परिणाम के लिए भी उत्तरदाई होते हैं ।

इसके प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं जो लोग सामाजिक गतिशीलता के कारण समाज में ऊंचा उठाना चाहते हैं । यदि उन्हें अपने लक्षण की प्राप्ति नहीं होती तो वह समझ में विरोधी उत्पन्न कर लेते हैं और बुद्धिमान व्यवस्था को तोड़ने का प्रार्थना करते हैं । फल स्वरूप प्रचलित समाज व्यवस्था के समर्थकों एवं विरोधों के बीच संघर्ष और पैदा हो जाता है । जाती देंगे इसका एक प्रमुख का उदाहरण है गतिशीलता

की दौड़ में लगे लोग अनावश्यक रूप से परेशान और चिंतित रहने लगते हैं। इससे सामान्य मानसिक रोगों में वृद्धि होती है समझ में गतिशीलता के नए पद प्राप्त करने वाले पुराने पद का पदाधिकारी के बीच तनाव मनमुटाव पैदा हो जाता है।

निष्कर्ष

एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र में पिछलापन बना रहेगा आज ग्रामीण क्षेत्रों को उनके प्रकार के उत्पादक कार्यों की ओर उन्मुख कर वहां एक नए उत्साह और स्मृति का संचार करना आवश्यक हो गया है। यह कार्य हो सकते हैं डेयरी उद्योग मुर्गी पालन मत्स्य पालन फल सब्जी उत्पादन और ग्रामीण उत्पादन के दो शहरी बाजारों विदेशी निर्यात बाजारों सहित के बीच संपर्क सूत्रों की रचना इस प्रकार कृषि उत्पादन में लगे निवेश अधिक प्रतिभा लाभ अर्जित करना संभव हो पाएगा। यही नहीं आधिकारिक संरचना जैसे सहायक एवं वितरण कृषक हिट नीतियों तथा कृषक समुदाय एवं राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायक है। आज हम पर्यावरण विकास ग्रामीण विकास को दो प्रथम प्रथम सम्मान का व्यवहार नहीं कर सकते। नई पर्यावरण मित्र औद्योगिक अधिकार का पद्धति को भी आवश्यक मानना चाहिए ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना होने पर इस विचारणीय विकास की ओर अग्रसर हो पाए इन विकल्पों में से प्रत्येक ग्राम समुदाय अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चयन कर सकता है। अतः हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध वीडियो में से सर्वश्रेष्ठ की पहचान कर उसे चुना ही होगा तात्पर्य ग्रामीण विकास के उन आयामों को सफल कर देश के विभिन्न क्षेत्र में प्रगति लाना ही इस प्रक्रिया का गति प्रदान महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है।

संदर्भ

अलका गौतम कृषि भूगोल शारदा पुस्तक भवन इस्लामाबाद 2009।

कायस्थ एल एम सिद रामबाबू डाइमेंशंस आफ एस का इंटीग्रेटेड रोलर डेवलपमेंट सी भु वाराणसी 1980।

डॉक्टर तिवारी आरसीएम डॉक्टर सिंह वन कृषि भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इस्लामाबाद 2006।

डॉ शकुंतला मीना ग्रामीण विकास की अवधारणा बढ़ाएं एवं शिक्षा की भूमिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन मॉडर्न मैनेजमेंट अप्लाइड साइंस एंड सोशल साइंस impact factor 6 3 4 0 volume 3 number 02 April 2 June 2021

नारायण एस 2005 ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया नाबार्ड वोकेशनल पेपर नंबर 38 डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मुंबई।

इंडियन फार्मर ए मिलियन स्टडी एकेडमिक फाउंडेशन नई दिल्ली

दूर्वा आदिवासी का सामाजिक पत्रिका 2012 सामाजिक संस्कृति धार्मिक राजनीतिक आर्थिक शिक्षा एवं पर्यावरण चेतना के संगठन एवं विकास के पद पर

सरकारी रिपोर्ट

प्लानिंग कमीशन २००२ सक्सेसफुल गवर्नेस इनिटिएटिवेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज : एक्सपेरिमेंसेस फ्रॉम इंडियन स्टेट्स

गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया इन कोआर्डिनेशन विथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेण्टर एंड उच्चप दिल्ली २००२ वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

बेसिक एनिमल हस्बंडारी एंड फिशरीज स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया